का घोटाला पकड़ा है। गत सप्ताह उक्त कम्पनी के चार बड़े अफसरों के निवास स्थानों पर भी छापे मारे गए और कई खाता-बहियाँ जब्त कर ली गई। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन बहियों से मूल्य कम दिखाकर दो करोड़ रुपये की हेराफेरी तथा चार अफसरों के नाम से जमा व निवेश के रूप में लगभग चालीस लाख रुपये के अवैध धन का पता चला है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा इस प्रकार के घोटालों तथा हेरा-फेरी करने के मामले प्रकाश में आये हैं जो सरकारी टैक्सों की चोरी करते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसी कम्पनियों को ब्लेक लिस्टेड कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करे।

(v) Re decision of Bangladesh Government to Sell properties of Indians in Bangladesh

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : The Government of Bangladesh have decided to sell by auction or otherwise dispose of their property by the end of this month.

When Indo-Pakistan war broke out in 1965, the Pakistan Government enacted the Defence of P.kistan Ordinance and made rules thereunder for taking over property of Indians in Pakistan as enemy property. The custodians were to manage the property vested in them but the ownership did not vest with them. But with the end of the war, following the Tashkent Accord, Pakistan did not release the vested property to the original owners.

Bangladesh emerged as a separate Independent nation state in 1971. There has never been any war between Bangladesh and India. On the contrary, there exists a Treaty of Friendship between the two countries. So there is no longer any scope for taking over fresh Indian property in Bangladesh and treating the same vested enemy property.

One should also take note of the fact that Pakistan Government took over some Indian property in East Pakistan, but not the properties of which the East Pakistan residents were in possession though som their co-shares had gone to India and become Indian citizens. The Bangladesh Government has directed its Revenue authorities to search out all such properties and take over them as vested property.

This action means the loss of thousands crores of rupees worth property by Indian owners, and also eviction from their housesteads and agricultural lands of millions of Hindus and other minorities.

I demand that a statement may be made by the Minister of External Affairs in this regard.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) ; It is very important, Sir. I hope somebody takes note of it.

(vi) Need to Check Uncontrolled Mining in Saur Valley in Pithoragarh

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मसूरी व दून वैली को लाईमस्टपेन कवेरीज से उत्पन्न भू-क्षरण व प्रदूषण के खतरे को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस एवं व्यावहारिक पहल हो भी नहीं पाई थी कि उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ अन्य स्थानों विशेषकर पिथौरागढ़ जनपद में सौर वैली के लिए भी अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है।

सौर वैली को पिथौरागढ़ शीर्ष पर मैग्नेसाइट खानों में हो रहे अव्यवस्थित खनन से खतरा पैदा हुआ है। पिथोरागढ़ में चंडाक व तड़ी नामक स्थानों में दो प्राइवेट कंपनीज को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा खनन की अनुमति दी गई है, परंतु इनके द्वारा खनन कानूनों का सतत उल्लंघन किया जा रहा है। खुले खनन,

ओपट कास्ट माइनिंग के साथ साथ अव्यवस्थित खनन भी किया जा रहा है। व्यर्थ अवशेष व मिट्टी के लुढकाने से नीचे की सुन्दर घाटी भू-क्षरण से प्रभावित हो रही है। लैंड रीक्लेमेशन के कार्य को भी नहीं किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के प्रदूषण से निकटवर्ती क्षेत्रों की वन संपत्ति नष्ट हो रही है।

मैं इस अव्यवस्थित खनन व प्रदूषण को रोकने हेतु राज्य सरकार के ध्यान में ला चुका हूं। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी लोकसभा में दो बार प्रश्न पूछ कर इस ओर दिला चुका हूं। परंतु अभीष्ट अभी भी अपेक्षित है। मैं पुन: केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

1208 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

(vii) Need to Apply Laws Relating to Minimum Wages and Working Conditions to Bidi Workers

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna): Chanderi, Guna, Sagar, Damoh, Jabalpur and Raipur etc. are big centres of bidi industry in M.P. Lakhs of workers, including a large number of women and children are employed in it. These workers are, however, an exploited lot. Though they are busy from dawn to dusk in rolling bidis, the wages they receive are quite low. A fairly large number of bidi workers become victims of tuberculosis and tend to develop hunch-back tendencies. The condition of bidi workers scattered in rural areas is still worse. They are at the mercy of 'sattedars' who act as agents of bidi units. They supply tobacco and tendu leaves to rural bidi workers and assess the quality of the bidis produced. They invariably reject at least ten per cent of a worker's output as 'sub-standard'' and thus deprive him or her of full payment for the output. Not much effort has been made so far to free the workers from the stranglehold of satterdars, as the Bidi Kings do not want to discontinue the Sattedari system. It enables them to escape responsibility for paying fair wages and providing various facilities to workers.

I, therefore, urge upon the Government to take steps to ensure that :—

(i) the laws regarding minimum wages and working conditions are enforced in bidi-making establishments ; and

(ii) the cooperatives of bidi-workers are set up to enable them to get adequate return for their labour.

(vii) Non-availability of Drinking Water and Electricity in Bihar

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : बिहार में विद्युत संकट स्थायी सा हो गया है। इधर एक सप्ताह के अन्दर इस संकट के कारण लगभग सभी जिलों के मुख्यालयों में पेयजल एवं रोशनी नहीं मिल रही है। रांची की हालत विगत 24 घन्टों से अति दयनीय हो गयी है। पेयजल एकदम बंद है। हैवी इंजीनियरी काम्पलेक्स को 40 मैगावाट के स्थान पर सिर्फ 10 मैगावाट बिजली मिल रही है। इसका उत्पादन भी संकट में पड़ गया है। इसके अतिरिक्त लगभग राज्य का सारा उद्योग बंद सा हो गया है।

बिजली के अभाव में विगत वर्ष खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। अभी रबी लगाने का समय है तो बिजली नहीं है। यह फसल भी नष्ट होने वाली हैं।

जब बिहार में विद्युत की क्षमता 945 मैगावाट है तो सप्लाई सिर्फ 150 मेगावाट की ही क्यों है ? की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय और तुरंत उचित मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जाय।